



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २४ जुलाई, १९९१/२ भाद्रप, १९१३

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २४ जुलाई, १९९१

क्रमांक एल० एल० आर०-डी०(६)८/९१-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०१ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख ९ जुलाई, १९९१ को यथा अनुमोदित भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९९१ (१९९१ का विधेयक संख्यांक ११) को वर्ष १९९१ के हिमाचल प्रदेश अधिनियम

संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 248(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
अमरेन्द्र लाल वैद्य,
सचिव (विधि) ।

भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 9 जुलाई, 1991 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के वार्षिक वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम। अधिनियम; 1991 है।

1927 का 16 2. भारतीय वन अधिनियम; 1927 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में — धारा 2 का संशोधन।

- (क) खण्ड (6) में अन्त में आए “और” शब्द का लोप किया जायेगा ;
 (ख) खण्ड (7) में “1” चिह्न के स्थान पर “; और” चिह्न और शब्द रखे जायेंगे;
 (ग) ऐसे संशोधित खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (8) जोड़ा जाएगा;
 अर्थात्:—

“(8) “यान” से पहियों वाला किसी भी प्रकार का वाहन अभिप्रेत है जो भूमि पर संचलन के लिए उपयोग किए जाने के योग्य है और इसके अन्तर्गत छकड़ा, ट्रालियायन और ट्रैलर है किन्तु इसके अन्तर्गत साईकल और पशु नहीं हैं।”

3. मूल अधिनियम की धारा 26, धारा 33 और धारा 42 में “छः मास” और “पांच सौ” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “दो वर्ष” और “पांच हजार” शब्द रखे जायेंगे। धारा 26, 33 और 42 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (2) और उप-धारा (3) रखी जायेंगी; अर्थात्:— धारा 52 का संशोधन।

“(2) किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को, यदि विश्वास करने का कारण है कि इमारती लकड़ी, (जलावन लकड़ी को छोड़कर) राल, खैर-लकड़ी; कट्या के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, के परिवहन के लिए यान का प्रयोग किया है या किया जा रहा है, तो वह, यान चालक या ऐसे यान के अन्य भारसाधक व्यक्ति से यान को रोकने की अपेक्षा कर सकेंगे और इसे इतनी देर तक खड़ा रखवाएगा, जितनी देर तक यान को अन्तर्वस्तु के परीक्षण और वाहन किए गए माल के सम्बन्धी सारे रिकार्ड जो सम्बन्धित, ऐसे चालक या यान के भारसाधक व्यक्ति के कब्जे में हैं, के निरीक्षण के लिए; व्यक्तिगत रूप से आवश्यक हों।

(3) इस धारा के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगाएगा कि उसका अभिग्रहण किया गया है, और; यथाशक्यशीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट :—

(क) जहां अपराध, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, इमारती लकड़ी; (जलावन लकड़ी को छोड़कर) राल, खैर-लकड़ी, कत्था से सम्बन्धित है जो कि राज्य सरकार की सम्पत्ति है, धारा 52-अ की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को; और

(ख) अन्य मामलों में, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, मैजिस्ट्रेट को भेजेगा।”

धारा 52-अ, 5. मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 52-अ और धारा और 52-आ 52-आ अन्तः स्थापित की जायेंगी; अर्थात् :—

का अन्तः

स्थापन।

“52-अ कतिपय मामलों में वन अधिकारी द्वारा अधिहरण:—

(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, जहां यह विश्वास करने का कारण है कि इमारती लकड़ी (जलावन लकड़ी को छोड़कर) राल, खैर-लकड़ी, कत्था के बारे में वन अपराध किया गया है, राज्य सरकार की सम्पत्ति है, वहां धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, किसी युक्तियुक्त धिलम्ब के बिना, अपराध करने में प्रयोग किए गए सभी औजारों; रस्मियों, जंजीरों, नावों, यानों सहित, इस निमित्त सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जो सहायक अरण्यपाल वन (जिसे इसमें इस के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) की पंक्ति से नीचे का न हो; प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी, धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन किसी इमारती लकड़ी (जलावन लकड़ी को छोड़कर) राल, खैर-लकड़ी, कत्था का जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, अभिग्रहण करता है या जहां ऐसी सम्पत्ति को उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है; यदि उसका समाधान हो जाता है, कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में वन विषयक अपराध किया गया है, तो ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, चाहे ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित किया गया है या नहीं, ऐसा अभिगृहीत सम्पत्ति के, ऐसा अपराध करने के लिये प्रयोग किए गये सभी औजारों; रस्मियों, जंजीरों, नावों, यानों सहित, अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(3) (क) जहां धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन अभिग्रहण आदेश पारित करने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो, कि जनहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह अधिहरण की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग को लोक नीलामी द्वारा विक्रीत करने का आदेश दे सकेगा।

(ख) जहां अधिहरण की गई कोई सम्पत्ति यथारोति उपर्युक्त में विक्रीत की जाये, तो उसका आगम, जहां, धारा 52-अ के अधीन किया गया अधिहरण आदेश, धारा 59 या 59-अ के अधीन किए गए आदेश द्वारा वातिल या अपास्त कर दिया जाता है, ऐसी नीलामी के व्यय या उससे सम्बन्धित अन्य अनुषांगिक व्यय की कटौती करने के पश्चात् उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे यह अभिगृहीत की गई थी;

जैसा भी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, संदत्त किया जायेगा।

52-आ. धारा 52-अ के अधीन अधिहरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस का जारी किया जाना,—

- (1) धारा 52-अ के अधीन, किसी इमारती लकड़ी (जलावन लकड़ी को छोड़ कर), राल, खैर-लकड़ी और कत्था, रस्मियों, जंजीरो, नावों या यानों के अधिग्रहण का आदेश उस व्यक्ति को जिसे इन्हें अधिग्रहीत किया गया है, सिवाये लिखित रूप में नोटिस देने और उसके आक्षेपों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, नहीं दिया जायेगा।
- (2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 52-अ के अधीन किसी औजार, रस्सी, जंजीर, नाव या यान के अधिहरण का आदेश नहीं दिया जायेगा यदि औजार, रस्सी, जंजीर, नाव या यान का स्वामी प्राधिकृत अधिकारी के समामानप्रद रूप में यह मानित कर देता है कि इमारती लकड़ी (जलावन लकड़ी को छोड़ कर), राल, खैर-लकड़ी और कत्थे के बहन के लिए, इसका प्रयोग स्वयं स्वामी की अपनी, उसके एजेंट, यदि कोई हो, और औजार, रस्सी जंजीर, नाव या यान के भारमाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकुलता के बिना, किया गया था और उन में से प्रत्येक ने इनके प्रयोग के विरुद्ध पूर्ण युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानी बरती थी।

6. मूल अधिनियम की धारा 53 में "मैजिस्ट्रेट" शब्द के पश्चात् किन्तु "के" शब्द से पूर्व "या धारा 52-अ की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी" शब्द, कोष्ठ, अंक और वर्ण अन्तःस्थापित किए जायेंगे। धारा 53 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 58 के आरम्भ में आए "मैजिस्ट्रेट" शब्द के पश्चात् "या ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं धारा 52-अ की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी" शब्द, कोष्ठ, अंक और वर्ण अन्तःस्थापित किए जायेंगे। धारा 58 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 59 में—

धारा 59 का संशोधन।

- (क) शीर्षक में "धारा 55" से पूर्व "धारा 52-अ," शब्द, अंक, वर्ण और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;
- (ख) विद्यमान धारा को उप-धारा एक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा ; और
- (ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) और उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 52-अ या धारा 59-अ के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उस क्षेत्र में अधेकारिता रखने वाले सब न्यायाधीश को, जिसमें उस सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया है, जिससे आदेश सम्बन्धित, अपील कर सकेगा और सब न्यायाधीश यथास्थिति, अपीलार्थी और प्राधिकृत अधिकारी या धारा 59-अ

के अधीन विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपीलिय आदेश का पुष्टीकरण, उपांतरण या बातिलिकरण करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन सन्न्यायाधीश का आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।”

धारा 59-अ 9. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 59-अ और धारा 59-आ का अन्तःस्थापन।

“59-अ पुनरीक्षण.—राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त वन अधिकारी जो अरण्यपाल वन की पंक्ति से नीचे का न हो, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 52-अ के अधीन पारित आदेश की तारीख से 30 दिन के अवसान से पूर्व, स्वप्रेरणा से उस आदेश के अभिलेख को मंगवा सकेगा और परीक्षण और ऐसी जांच कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं किया जायेगा।

59-आ दण्डनियम मामलों में अधिकारिता का वर्जन.—जब कभी किसी इमारती लकड़ी (जलावन लकड़ी को छोड़कर) राल, खैर-लकड़ी कचरे का अपराध करने में प्रयोग किए गए किसी अजगर, रस्सी, जंजीर, नाव या यान सहित धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया जाता है, तो धारा 52-अ की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या धारा 59-अ के अधीन विशेष रूप से सशक्त अधिकारी या धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाले सन्न्यायाधीश को, ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा, कब्जे परिदान, पिटाने या विनरण के सम्बन्ध में आदेश देने की अधिकारिता, प्राप्त होगी और, इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अन्य कार्यालय, न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण को ऐसी अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।”

धारा 60 का 10. मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 60 का प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन। किया जायेगा :—

“60. जब किसी सम्पत्ति के अधिहरण के लिए, यथास्थिति, धारा 52-अ या धारा 55 या धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है या जहाँ धारा 59-अ के अधीन दिए गए पुनरीक्षण आवेदन पर, अधिहरण के लिए ऐसा आदेश, अपास्त नहीं किया गया है, और धारा 59 द्वारा, ऐसे आदेश से अपील के लिए, परिसीमित काल बीत गया है, और ऐसी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है या जब ऐसी अपील के प्रस्तुत किए जाने पर, अपील न्यायालय, ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग के बारे में ऐसे आदेश की पुष्टि कर देता है, तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग या, यदि यह धारा

52-अ की उप-धारा (3) के अधीन विक्रीत की गई है तो इसका विक्रय आगम, बिलगमों से रहित सरकार में निहित होगा।”

11. मूल अधिनियम की धारा 61 में “सम्पत्ति” शब्द के पश्चात् किन्तु “को” शब्द से पूर्व “जो सरकार की नहीं है, और ऐसी सम्पत्ति के बारे में लगाए गए किसी प्रकार के प्रत्याहरण” शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे। धारा 61 का संशोधन।
12. मूल अधिनियम की धारा 67 में आए “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)” शब्दों, कोष्ठ और अंकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” शब्द, कोष्ठ और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे। धारा 67 संशोधन

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 15 of 1991.

THE INDIAN FOREST (HIMACHAL PRADESH SECOND AMENDMENT) ACT, 1991

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 9TH JULY, 1991)

AN

ACT

further to amend the Indian Forest Act, 1927 (Central Act No. 16 of 1927) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Indian Forest (Himachal Pradesh Second Amendment) Act, 1991.

Amendment of section 2. 2. In section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (hereinafter called the principal Act)—

- (a) in clause (6), the word “and” occurring at the end shall be omitted;
- (b) in clause (7), for the sign “.”, the sign and word “; and” shall be substituted; and
- (c) after clause (7) so amended, the following clause (8) shall be added, namely :—

“(8) “Vehicle” means a wheeled conveyance of any description which is capable of being used for movement on land and includes a cart, trolley vehicle and a trailer but does not include bicycle and cattle.”.

Amendment of sections 26, 33 and 42. 3. In sections 26, 33 and 42 of the principal Act, for the words “six months” and “five hundred”, the words “two years” and “five thousand” shall be substituted respectively.

Amendment of section 52. 4. For sub-section (2) of section 52 of the principal Act, the following sub-sections (2) and (3) shall be substituted, namely :—

“(2) Any Forest Officer or Police Officer may, if he has reasons to believe that a vehicle has been or is being used for the transport of timber (excluding fuelwood) resin, khair wood and katha in respect of which a forest offence has been or is being committed, require the driver or other person-in-charge of such vehicle to stop the vehicle and cause it to remain stationary as long as may reasonably be necessary to examine the contents in the vehicle and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person-in-charge of the vehicle.

(3) Every Officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been seized, and shall, as soon as may be, make a report of such seizure—

(a) where the offence, on account of which the seizure has been made, is in respect of timber (excluding fuelwood), resin, khair wood and katha which is the property of the State Government, to the concerned authorised officer under sub-section (1) of section 52-A; and

(b) in other cases, to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure is made.”.

5. After section 52 of the principal Act, the following sections 52-A and 52-B shall be inserted, namely :—

Insertion of sections 52-A and 52-B.

“52-A. *Confiscation by Forest Officers in certain cases* .—(1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, where a forest offence is believed to have been committed in respect of timber (excluding fuelwood), resin, khair wood and katha, which is the property of the State Government, the Officer seizing the property under sub-section (1) of section 52 shall without any unreasonable delay produce it, together with all tools, ropes, chains, boats or vehicles used in committing such offence before an Officer, authorised by the State Government in this behalf, by notification published in the Official Gazette, not below the rank of an Assistant Conservator of Forests (hereinafter referred to as the authorised officer).

(2) Where an authorised officer seizes under sub-section (1) of section 52 any timber (excluding fuelwood) resin, khair wood and katha, which is the property of the State Government, or where any such property is produced before an authorised officer under sub-section (1), once he is satisfied that a forest offence has been committed in respect of such property, such authorised officer may, whether or not a prosecution is instituted for the commission of such offence, order confiscation of the property so seized together with all tools, ropes, chains, boats or vehicles used in committing such offence.

(3) (a) Where the authorised officer, after passing an order of confiscation under sub-section (2), is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order confiscated property or any part thereof to be sold by public auction.

(b) Where any confiscated property is sold as aforesaid, the proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such auction or other incidental expenses relating thereto, shall where the order of confiscation made under section 52-A is set aside or annulled by an order under section 59 or section 59-A, be paid to the owner thereof or the person from whom it was seized as may be specified in such order.

52-B. Issue of show cause notice before confiscation under section 52-A.—(1) No order confiscating any timber (excluding fuelwood) resin, khair wood and katha, ropes chains, boats or vehicles shall be made under section 52-A except after notice in writing to the person from whom it is seized and considering his objections, if any:

Provided that no order confiscating a motor vehicle shall be made except, after giving notice in writing to the registered owner thereof, if in the opinion of the authorised officer it is practicable to do so, and considering his objections, if any.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any tool, rope, chain, boat or vehicle shall be made under section 52-A if the owner if the tool, rope, chain, boat or vehicle proves to the satisfaction of the authorised officer that it was used in carrying the timber (excluding fuelwood), resin, khair wood and katha without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person-in-charge of the tool, rope, chain, boat or vehicle and that each of them had taken all reasonable and necessary precaution against such use."

Amendment
of section
53.

6. At the end of section 53 of the principal Act but before the sign ".", the words, brackets, figures, sign and alphabet "or before the authorised officer under sub-section (1) of section 52-A" shall be inserted.

Amendment
of section
58.

7. After the words "The Magistrate" occurring in the beginning of section 58 of the principal Act, the words, brackets, figures and alphabet "or subject to such rules as may be prescribed, the authorised officer under sub-section (1) of section 52-A" shall be inserted.

Amendment
of section
59.

8. In section 59 of the principal Act—

- (a) in the heading after the words "orders under section" but before the figure "55", the figure, alphabet and sign "52-A," shall be inserted;
- (b) the existing section shall be re-numbered as sub-section (1); and
- (c) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section (2) and sub-section (3) shall be added, namely:—

"(2) Any person aggrieved by any order passed under section 52-A or section 59-A may, within thirty days from the date of communication to him of such order, appeal to the Sessions Judge having jurisdiction over the area in which the property to which the order relates has been seized and the Sessions Judge shall, after giving an opportunity to the appellant and the authorised officer or the officer specially empowered under section 59-A, as the case may be, to be heard, pass such order as he may think fit confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(3) The order of the Sessions Judge under sub-section (2) shall be final and shall not be questioned in any Court of law."

9. After section 59 of the principal Act, the following sections 59-A and 59-B shall be inserted, namely:—

Insertion of sections 59-A and 59-B.

“59-A. *Revision.*—Any forest officer not below the rank of Conservator of Forests, specially empowered by the State Government in this behalf by notification published in the Official Gazette, may, before the expiry of thirty days from the date of order of the authorised officer under section 52-A, *suo-moto* call for and examine the records of that order and may make such enquiry or cause such enquiry to be made and may pass such orders as he deems fit:

Provided that no order prejudicial to a person shall be passed under this section without giving him an opportunity of being heard.

59-B. *Bar of jurisdiction in certain cases.*—Whenever any timber (excluding fuelwood), resin, khair wood and katha together with any tool, rope, chain, boat or vehicle used in committing any forest offence is seized under section 52, the authorised officer under sub-section (1) of section 52-A or the officer specially empowered under section 59-A or Sessions Judge hearing an appeal under sub-section (2) of section 59 shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) or in any other law for the time being in force, any other officer, Court, Tribunal or authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to custody, possession, delivery, disposal or distribution of such property.”

10. For section 60 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 60.

“60. When an order for the confiscation of any property has been passed under section 52-A or section 55 or section 57, as the case may be, or where on revision application made under section 59-A such order for confiscation has not been set aside, and the period limited by section 59 for an appeal from such order has elapsed, and no such appeal has been preferred or when, on such an appeal being preferred, the Appellate Court confirms such orders in respect of the property or a portion of such property, such property or such portion thereof, or if it has been sold under sub-section (3) of section 52-A, the sale proceeds thereof, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.”

11. After the figure “52” but before the sign “.” occurring at the end of section 61 of the principal Act, the signs and words “, which is not the property of the Government, and the withdrawal of any charge made in respect of such property” shall be inserted.

Amendment of section 61.

12. For the words, brackets and figures “the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898)” occurring in section 67 of the principal Act, the words, brackets and figures “the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” may be substituted.

Amendment of section 67.

